ध्वजपोत सरकारी कार्यक्रम
(Flagship Government Programs)

☞ फरवरी, 2019 में किस राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की गई है?
— हरियाणा।

☞ मार्च, 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने किस नाम की एक जल संरक्षण योजना का शुभारंभ बंगलुरू में किया? **— 'जल अमृत'।**

☞ 5 मार्च, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रंबधन प्रणाली (CIBMS) के तहत बोल्ड-क्यूआईटी (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआटी इंटरसेप्शन टेक्निक) परियोजना का उद्घाटन कहां किया? **— असम के धुषरी जिले में।**

☞ 28 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त फेम इंडिया ओपन 3 वर्षों के लिए किस तिथि से प्रारंभ होगी?
— 1 अप्रैल, 2019 से।

☞ 28 फरवरी, 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना हेतु वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि तक कुल कितनी राशि के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है? **— 1969.50 करोड़ रुपये।**

☞ 28 फरवरी, 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना (नेपाल भाग) के ट्रांसमिशन घटक में कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की?
— 1236.13 करोड़ रुपये।

☞ 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ कहां किया? **— गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)।**

☞ फरवरी, 2019 में किस राज्य में शहर युवाओं को प्रतिवर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने हेतु 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' शुरू की गई है? **— मध्य प्रदेश।**

☞ फरवरी, 2019 में टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु VIVID 2019 के तीसरे संस्करण में कौन-सी योजना शुरू की गई है?
— प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (TIDE2.0) योजना।

☞ भारत के पहले पुलिस ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का क्या नाम है? **— केपी-बीओटी।**

☞ 19 फरवरी, 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमोदित की गई योजना का क्या नाम है?
— किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान।

☞ 19 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण को मार्च, 2019 के बाद भी (पीएमएवाई-जी चरण II) जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इस चरण के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुल कितने मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? **— 1.95 करोड़।**

☞ 19 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत किस बाह्य सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई?
— राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना।

☞ फरवरी, 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजनाओं से कितने मेगावॉट की संचयी क्षमता हासिल करने हेत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की गई?
— 40,000 मेगावॉट।

☞ 19 फरवरी, 2019 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रेशम क्षेत्र के विकास हेतु पूर्वोत्तर में 4 परियोजनाओं का शुभारंभ किन राज्यों में किया गया?
— मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम।

☞ केंद्र सरकार ने 2017-2031 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वन्यजीवन कार्ययोजना के तहत संरक्षण हेतु कितने तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की है? **— 106 ।**

☞ स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित 'इको सर्किट का विकास : पठनमथिट्टा - गवी - वागामोन - थेक्कडी' परियोजना किस राज्य से संबंधित है? **— केरल।**

☞ 1 अप्रैल, 2019 से किस राज्य में 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' शुरू की जाएगी? **— बिहार।**

☞ 15 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। यह बांध किस नदी पर स्थित है? **— धसान नदी।**

☞ 13 फरवरी, 2019 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक ने आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का नाम है? **— ई-औषधि।**

☞ फरवरी, 2019 में कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित मेगा इवेंट 'सर्जिंग सिल्क' के दौरान लांच किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? **— ई-कोकून।**

☞ 9 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग और आगे के क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु किस सुरंग परियोजना का शिलान्यास किया? **— सेतना सुरंग परियोजना।**

☞ 7 फरवरी, 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में इंदिरा गृह ज्योति योजना को शुरू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? **— मध्य प्रदेश।**

☞ फरवरी, 2019 में शुरू की गई 'प्रकाश गृह परियोजना चैलेंज' के तहत 'वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चैलेंज - भारत' GHTC-INDIA) के अंतर्गत प्रकाश गृह परियोजनाओं के निर्माण हेतु देशभर में कितने स्थलों का चयन किया जाएगा? **— 6।**

☞ 11 फरवरी, 2019 को भारत सरकार की क्रेडिट लाइन (LOGs) के तहत सौर परियोजनाओं हेतु बिजनेस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन चेन्नई (तमिलनाडु) में किस बैंक के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया? **— एक्जिम (EXIM) बैंक।**

☞ किस राज्य में मिनीमात अमृत नल-जल योजना, मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना और राजीव गांधी सर्वजल योजना शरू की जाएगी? **— छत्तीसगढ़ में।**

☞ असम सरकार सस्ती पोषण और पोषाहार सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत कितने रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएगी? **— 1 रुपये प्रति किलो।**

☞ इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजनान्तर्गत 45 वर्ष तक की आयु की महिला के पति के निधन होने पर असम सरकार उसे तत्कालिक पारिवारिक सहायता के रूप में एकमुश्त कितनी राशि प्रदान करेगी? **— 25,000 रुपये।**

☞ असम सरकार किस योजनान्तर्गत ऐसे सभी समुदायों को शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करेगी, जहां शादी के समय सोना देने की प्रथा है? **— अरुंधती योजना।**

☞ अरुंधती योजना का नाम किस महान ऋषि की पत्नी अरुंधती के नाम पर रखा गया है? **— वशिष्ठ।**

☞ 624 मेगावॉट की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? **— जम्मू और कश्मीर** (किश्तवाड़ में)।

☞ डीएएच पनबिजली परियोजना (9 मेगावॉट) कहां स्थित है? **— दाह में।**

☞ 8 फरवरी, 2019 को 3 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि के योगदान के साथ एक समर्पित 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया? **— 97.85 करोड़ रुपये।**

❑ प्रमुख योजनाएं

❑ कन्या सुमंगला योजना

☞ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2019-20 में बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की घोषणा। (7 फरवरी, 2019)

☞ इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी करने पर चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

☞ इस योजना हेतु बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

❑ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

☞ केंद्रीय बजट 2019-20 में वित्त मंत्री द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा। (1 फरवरी, 2019)

☞ योजनांतर्गत सरकार दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करेगी।

☞ यह सहायता राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

❑ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

☞ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह के अवसर पर 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' योजना का शुभारंभ। (24 जनवरी, 2019)

☞ यह योजना पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों यथा-नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री इत्यादि को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।

☞ इसके तहत उन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

☞ इस दौरान उन्हें प्रतिदिन 250 रु. की दर से भत्ता व ट्रेनिंग के पश्चात प्रमाण-पत्र तथा 10 हजार रु. तक का टूल किट प्रदान किया जाएगा।

❑ प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना

☞ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन के दौरान 'प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना' को तैयार किए जाने संबंधी जानकारी दी गई। (22 जनवरी, 2019)

☞ इस योजना के तहत चयनित भारतीय प्रवासियों के एक समूह को केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक स्थानों की यात्रा कराएगी।

☞ सरकार उनके देश से हवाई यात्रा सहित सभी खर्च वहन करेगी।

☞ योजनांतर्गत 45-65 वर्ष की आयु के सभी भारतीय मूल के लोग आवेदन कर सकते हैं।

☞ चयन में मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और जमैका में रहने वाले गिरमिटिया (भारतीय श्रमिकों के वंशज) लोगों को वरीयता दी जाएगी।

☞ प्रधानमंत्री द्वारा मॉरीशस में प्रथम अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी उत्सव के आयोजन की भी घोषणा की गई।

❑ एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना

☞ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने का निर्णय। (18 जनवरी, 2018)

☞ योजनांतर्गत सरकार चिह्नित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने और विभिन्न राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन विकास के नए अवसरों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए 'एक जनपद-एक उत्पाद' से जुड़े हुए उत्पादकों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों तथा निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

❑ वन फैमिली, वन जॉब योजना

☞ सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा 'वन फैमिली, वन जॉब' योजना का शुभारंभ। (12 जनवरी, 2019)

☞ इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

☞ इस तरह की योजना को प्रारंभ करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है।

❑ आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

☞ **अनुमोदन—** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च, 2018 को आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया।

☞ **प्रावधान—** योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों (लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों) को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपये वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

☞ इस योजना के तहत वे परिवार, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के हों या जिनके परिवार में कोई 16-59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हों या सभी सदस्य दिव्यांग हों या वह परिवार भूमिहीन हो या वह मैला ढ़ोने का कार्य करता हो या बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो आदि योजना के पात्र हैं।

☞ यह योजना सभी सूचीबद्ध (सरकारी/निजी) अस्पतालों में प्रभावी रहेगी।

❑ निर्वाचन बॉण्ड योजना, 2018

☞ **प्रारंभ—** निर्वाचन बॉण्ड योजना, 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी, 2018 को अधिसूचित की गई।

☞ **पात्रता—** भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉण्ड खरीदने के पात्र होंगे।

☞ निर्वाचन बॉण्ड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोक सभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम-से-कम 1 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो।

☞ **प्रावधान—** निर्वाचन बॉण्ड 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे।

☞ इन बॉण्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता है, तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है।

☞ बॉण्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है।

❑ राष्ट्रीय पोषण मिशन

☞ **स्वीकृति—** देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर, 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई।

☞ **लक्ष्य—** राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2 प्रतिशत वार्षिक की कमी लाना है।

☞ रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

☞ **प्रावधान—** इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू कराया जाएगा, जिसके तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।

☞ वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर तीन वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9046.17 करोड़ रुपये के बजट का प्राक्धान किया गया है।

☞ इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50 प्रतिशत भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50 प्रतिशत आईबीआरडी (IBRD) अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाएगा।

☞ बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों हेतु 60 : 40 के अनुपात में, विशेष राज्यों हेतु 90 : 10 के अनुपात में विभाजित होगा।

☞ बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत सहायता केंद्र द्वारा दी जाएगी।

☞ इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

❑ गंगा ग्राम परियोजना

☞ **प्रारंभ—** गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन' में किया गया। यह परियोजना 'नमामि गंगे' के अंतर्गत है।

☞ **प्रावधान—** इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाएगा।

☞ इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सकीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

☞ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है।

❑ सौभाग्य योजना

☞ **प्रारंभ—** 25 सितंबर, 2017 को पं. दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) का शुभारंभ किया गया।

☞ **उद्देश्य—** सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है।

☞ **प्रावधान—** योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्सन उपलब्ध कराया जाएगा।

☞ इस परियोजना हेतु कुल 16320 करोड़ रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 14025 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2295 करोड़ रुपये) का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

☞ इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

☞ योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) द्वारा किया जाएगा।

❑ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

☞ **शुभारंभ—** प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से किया गया।

☞ **प्रावधान—** यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है।

☞ प्रारंभ में यह एक वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे वर्ष 2019-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

☞ योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है।

☞ इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुस्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है।

❑ 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान

☞ **शुभारंभ—** 14 अप्रैल, 2016 (डा. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर), महू (मध्य प्रदेश) से। अवधि 14-24 अप्रैल, 2016

☞ यह अभियान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों एवं पंचायतों के सहयोग से चलाया गया।

विभिन्न कार्यक्रम

☞ सामाजिक समरसता कार्यक्रम (14-16 अप्रैल, 2016)

☞ ग्राम किसान सभा (17-20 अप्रैल 2016)

☞ ग्राम सभा (21-24 अप्रैल 2016)

❑ मा कार्यक्रम (MAA-Mother's Absolute Affection)

☞ **शुभारंभ—** 5 अगस्त, 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।

☞ **लक्ष्य—** स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना।

☞ **वित्तीयन—** मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपये का आवंटन (प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपये)

❑ उड़ान : क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना

☞ **शुभारंभ—** 21 अक्टूबर, 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गणपति राजू द्वारा, नई दिल्ली में।

☞ **लक्ष्य—** आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाओं को सुलभ बनाना।

☞ **टैगलाइन—** 'उड़े देश का आम नागरिक'।

☞ **पहली उड़ान—** 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से दिल्ली।

☞ **कार्यकारी एजेंसी—** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (**Airport Authority of India**)

☞ इस योजना के तहत 500 किमी. की 1 घंटे की यात्रा अथवा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट के सफर का किराया अधिकतम 2500 रु. निश्चित किया गया है।

❑ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

☞ **घोषणा–** 13 जनवरी, 2016

☞ **प्रारंभ–** खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी।

☞ **लक्ष्य–** प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।

☞ **फसल कवरेज–** इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं।

☞ **किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि–** खरीफ की फसल पर 2.0 प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत। प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति, दोनों में जो कम हो, का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा।

❑ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

☞ **अनुमोदन–** 1 जुलाई, 2015

☞ इस योजना में 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम', 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' तथा 'खेत में जल प्रबंधन' को मिला दिया गया है।

☞ **लक्ष्य–** उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन।

☞ **कार्यान्वयन–** राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं।

☞ इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50,000 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

☞ राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे।

❑ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

☞ **प्रारंभ–** 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया।

☞ इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने **'स्वस्थ धरा, खेत हरा'** का नारा भी दिया।

☞ **लक्ष्य–** मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

☞ अगले 3वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।

☞ ये कार्ड प्रत्येक तीन वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे।

☞ यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देख-रेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

❑ अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

☞ **प्रारंभ–** 25 जून, 2015 को, नई दिल्ली में

☞ **लक्ष्य–** 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों, में, परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

☞ **प्रमुख क्षेत्र–** 1. जलापूर्ति, 2. सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन, 3. बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन जिसने शहरों की भव्यता बढ़े।

☞ **वित्तीय–** वर्ष 2015-16 से पांच वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपये।

❑ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

☞ **प्रारंभ–** 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से।

☞ **लक्ष्य–** लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना।

☞ प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात (SRB : Sex Ratio at Birth) में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था।

☞ वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है।

☞ यह तीन मंत्रालयों–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।

❑ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

☞ **प्रारंभ–** 1 मई, 2016 को बलिया (उ.प्र.) से।

☞ **लक्ष्य–** गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना।

☞ **आदर्श वाक्य–** 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन'

☞ योजना के अंतर्गत तीन वर्षों (2016-19) में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई-गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसे बजट, 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया।

☞ यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

❑ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

☞ **प्रारंभ–** 25 जुलाई, 2015 को पटना में।

☞ **लक्ष्य–** ग्रामीण विद्युतीकरण, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का अलगाव करना

☞ **नोडल एजेंसी–** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.।

☞ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है।

❑ सांसद आदर्श ग्राम योजना

☞ **प्रारंभ–** 11 अक्टूबर, 2014 (लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर)

☞ **लक्ष्य–** ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा ग्राम समुदाय में सामाजिक एकजुटता हेतु लोगों को प्रेरित करना।

☞ ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है।

☞ **प्रावधान–** प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 तक तीन गांवों को बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु गोद लेंगे।

☞ इनमें से वर्ष 2016 तक एक आदर्श गांव को तथा मार्च, 2019 तक दो और आदर्श ग्रामों को विकसित करनें का लक्ष्य है।

☞ ग्राम पंचायत विकास की आधारभूत इकाई होगी।

☞ इसके बाद पांच और गांवों (प्रत्येक वर्ष एक) को वर्ष 2024 तक विकसित करना है।

☞ इस योजना के लिए अलग से वित्तीयन नहीं किया गया है, बल्कि पहले से ही अस्तित्व में रहने वाली योजनाओं यथा– इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा तथा पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट फंट आदि के वित्त के प्रयोग का प्रावधान है।

❑ प्रधानमंत्री जन-धन योजना

☞ **प्रारंभ–** 28 अगस्त, 2014 को, 'मेरा खाता, भाग्य विधाता' आदर्श वाक्य के साथ।

☞ **लक्ष्य–** वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन।

☞ **घटक–** वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता।

☞ वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना।

☞ रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।

☞ **उपलब्धि–** योजना के तहत 4 अप्रैल, 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग 81 प्रतिशत खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए है।

❑ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

☞ **प्रारंभ–** 8 अप्रैल, 2015 को

☞ MUDRA (Micro Unit Development and Refinance Agency) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में।

☞ **लक्ष्य–** 'धनहीन को धन प्रदान करना' (Funding to The Unfunded)।

☞ पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना।

☞ **सुविधा–** योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

1. शिशु उद्योग–50 हजार रुपये तक।
2. किशोर उद्योग–50 हजार से 5 लाख रुपये तक।
3. तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपये तक।

❑ अटल पेंशन योजना

☞ **प्रारंभ–** 1 जून, 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय।

☞ **लक्ष्य–** निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

☞ अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000-5000 के बीच पेंशन का प्रावधान।

☞ **पात्रता–** 18-40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक पात्र।

☞ अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष।

☞ 5 वर्षों तक अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपया प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का वहन सरकार द्वारा।

❑ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

☞ **प्रारंभ–** 9 मई, 2015 को कोलकाता से

☞ **लक्ष्य–**सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि 1 वर्ष (1 जून से 31 मई)

☞ **पात्रता–** 18-70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक पात्र होंगे।

☞ प्रीमियम राशि 12 रु./वर्ष (स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से)।

☞ दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपया, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपया।

❑ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

☞ **प्रारंभ–** 9 मई, 2015

☞ **लक्ष्य–** जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

☞ **पात्रता–** 18-50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति।

☞ प्रीमियम राशि 330 रुपये।

☞ जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये।